Name of News paper	HINDUSTAN
Edition	LUCKNOW
Date	19.12.2021
Page no.	02

हिन्दुस्तान 02
लखनऊ • रविवार • 19 दिसंबर 2021

बिजली महकमे में चल रहा है अस्थाई डिस्कनेक्शन का खेल

राज्य मुख्यालय | प्रमुख संवाददाता

बिजली महकमे में अस्थाई रूप से काटे गए कनेक्शनों को तय समयसीमा में स्थाई रूप से नहीं काटे (विच्छेदित) जाने की लापरवाही अनवरत चली आ रही है। मार्च 2019 में 520772 ऐसे कनेक्शन मिले जो कि छह माह से भी अधिक अवधि से विच्छेदित थे।

इन कनेक्शनों को स्थाई रूप से विच्छेदित नहीं किया गया था। सीएजी की नजरें इस खामी पर पड़ी। इस मामले में सीएजी की सीधी सपाट टिप्पणी है कि बिजली कंपनियां निर्धारित छह माह के अंदर अस्थाई रूप से विच्छेदित कनेक्शनों को स्थाई रूप से विच्छेदित करने में विफल रही हैं।

मैनुअल बिलिंग से फायदा ले रहे हैं 87,856 कर्मचारी

मार्च 2019 के आंकड़ों से ही सीएजी की एक अन्य रिपोर्ट चौंकाने वाली है। इस समय तक बिजली महकमे का पूरा बिलिंग सिस्टम कंप्यूटराईज्ड हो गया था। इसके बावजूद 135102 मामले मैनुअल (हाथ से) बिलिंग के मिले। इसमें सबसे बड़ी संख्या 65.03 फीसदी यानी 87856 विभागीय कर्मचारियों के कनेक्शन थे। सीएजी की समझ में भी यह नहीं आया कि उ.प्र. पावर कारपोरेशन और बिजली कंपनियों के कर्मियों के बिल मैनुअल क्यों बनाए जा रहे हैं।

Name of News paper	DAINIK JAGRAN
Edition	LUCKNOW
Date	18.12.2021
Page no.	COVER PAGE

दैनिक जागरण लखनऊ, 18 दिसंबर, 2021

आइटी बिलिंग प्रणाली दुरुस्त न होने से डिस्काम को 18 करोड़ की चपत

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने बिजली उपभोक्ताओं को पारदर्शी तरीके से बिल मुहैया कराने का प्रयास जरूर किया लेकिन, अब तक आइटी बिलिंग प्रणाली दुरुस्त नहीं हो सकी है। शुक्रवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रस्तुत की गई भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कैग) रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य विद्युत वितरण उपक्रम यानी डिस्काम को एक वित्तीय वर्ष 2018-19 में ही 18 करोड़ से अधिक की चपत लगी। साथ ही बिलिंग में मानवीय हस्तक्षेप को खत्म करने का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो सका है।

यूपी पावर कारपोरेशन कंपनी के पास दो आइटी आधारित राजस्व बिलिंग प्रणालियां ऊर्जा वितरण एवं सेवा प्रबंधन (ईडीएसएमएस) हैं, इनका प्रदेश के 168 चयनित शहरों में पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास व सुधार कार्यक्रम (आर-एडीपीआरपी) के तहत जून 2015 से संचालन किया जा रहा है। इसी तरह से एम पावर को सितंबर 2017 को संचालित किया गया, जो गैर आर-एडीपीआरपी क्षेत्रों में शुरू किया गया। रिपोर्ट में लिखा है कि 31 मार्च 2019 को 2.58 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं का दोनों प्रणालियों से बिल किया जाना था, इनमें से एक लाख 35 हजार 102 उपभोक्ताओं का मैनुअली बिल किया गया।